सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-263 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, बुधवार 28 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

कोरोना वैरियंट घातक नहीं, लेकिन लक्षण नजर आएं तो चिकित्सक से परामर्श लें-गजेन्द्र सिंह खींवसर

जयपुर। देशभर में कोरोना के केस सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान मे सामने आया वैरियंट घातक नहीं है, लेकिन आमजन खांसी-जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सामान्य एहतियात बरतते हुए चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जांच एवं उपचार लें। खींवसर ने कहा कि संवेदनशील वर्ग जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी एवं बच्चे कोरोना के केसेज को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आईएलआई के लक्षण नजर आने पर चिकित्सक से परामर्श लें एवं भीड़-भाड़ से बचें। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं बताया है, लेकिन चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार के लिए आवश्यक इंतजाम रखे जाएं, ताकि आईएलआई लक्षणों के मरीजों को जरूरी जांच एवं उपचार मिल सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने ऑक्सीजन प्लांट्स की क्रियाशीलता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के साथ ही बंद ऑक्सीजन प्लांट्स को शीघ्र ठीक करवाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से कोरोना के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 9 केस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 2 केस एम्स जोधपुर में, 2 सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में तथा 4 केस बी लाल लैब जयपुर एवं 1 केस अनाविक डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर में आया है। इस वर्ष अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। इनमें अजमेर में 2, बीकानेर में एक, डीडवाना में 3, जयपुर में 13, जोधपुर में 6, फलौदी में 1, सवाई माधोपुर में एक, उदयपुर में 4 एवं एक अन्य केस सामने आया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को मिल रही गति

सीएम भजनलाल शर्मा की तत्परता से क्रियान्विति हो रही सुनिश्चित

चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने जारी की स्वीकृति

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में परियोजना के प्रथम चरण में चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से स्वीकृति के बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ (कूल नदी), महलपुर (पार्वती नदी) व नवनेरा (कालीसिंध नदी) बैराज का पानी चम्बल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा तथा बीसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लम्बाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपल्दासमेल गांव और दूसरा छोर बून्दी के गुहाटा गांव से जुडेगा।

इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बून्दी से गुजर रहे कोटा-सवाईमाधोपुर हाईवे से पक्की सड़क द्वारा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही, परियोजना में नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण की कार्यवाही को गति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 9400 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर योजना की क्रियान्विति शुरू कर दी गई है। इस चरण में पैकेज-2 के अन्तर्गत चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है।

शौर्य गाथा के रंग' का आयोजन आज

जयपुर। महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आगामी 28 मई को जयपुर में 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रेम सिंह बनवासा ने पीएम मोदी और महाराणा प्रताप को एक जैसा बता दिया। पढ़ें पूरी खबर...।

महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनकी वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा आगामी 28 मई को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम में राज्य के कई अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

वीरता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देने का प्रयास

कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महाराणा प्रताप के अद्वितीय जीवन और शौर्यगाथा को स्मरण करना है। साथ ही युवाओं में राष्ट्रभक्ति, आत्मबलिदान और सांस्कृतिक गौरव की भावना जागृत की जाएगी। बनवासा ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जैसे मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की अस्मिता के लिए हर मोर्चे पर निडरता से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और नरेंद्र मोदी दोनों में राष्ट्र के प्रति समर्पण, स्वाभिमान और त्याग की भावना समान है।

फिल्म, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजेगा मंच

'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक विशेष फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध कवि ओजपूर्ण कविताओं के माध्यम से महाराणा प्रताप की वीरता और आत्मबलिदान की गाथा प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक मंच होगा, बल्कि इतिहास को जीवंत रूप में महसूस कराने वाला अनुभव भी बनेगा।

सामाजिक चेतना जगाने वाली पहल

प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि महाराणा प्रताप फाउंडेशन समय-समय पर शौर्यगाथा संगोष्ठियां, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित करता रहा है। इन आयोजनों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से बाल और युवा वर्ग को महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरित करना है।

कार्यक्रम में इन अतिथियों की रहेगी उपस्थिति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य और जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी उपस्थित रहेंगे।

जयपुर सेप्टिक टैंक हादसा-मानवाधिकार आयोग ने लिया सख्त एक्शन

जयपुर। राजधानी जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से चार मजदूरों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

इस दर्दनाक हादसे पर अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और जयपुर जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मानव जीवन की कीमत पर लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

राजस्थान में उपचुनाव के 6 माह बाद ही क्यों भिड़े बीजेपी रूऔर पूर्व प्रत्याशी? जमकर चला 'पोस्टर वार'; जानें

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कंपनी से जवाब मांगा है। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए और कंपनी अपनी ओर से भी परिजनों को उचित क्षतिपूर्ति दे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून 2025 को होगी।

जयपुर रोड पर दर्दनाक हादसा-तेज रफ्तार कार ने छीनी मां की जिंदगी, पिता-पुत्र गंभीर घायल

जयपुर। अजमेर 7 जयपुर रोड पर सोमवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि उसका पति और 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तीनों बाइक से किशनगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। घुघरा के पास एक तेज रफ्तार कार ने गलत दिशा से आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

मृतक महिला की पहचान सोनू (28) पत्नी चरणदास, निवासी हरिजन बस्ती, रामगंज यूआईटी कॉलोनी के रूप में हुई है। वहीं उसका पति चरणदास (31) और बेटा दीपांशु (10) गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

तेज रफ्तार और लापरवाही बना हादसे का कारण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। जैसे ही उसने नियंत्रण खोया, बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और बेटा सड़क पर बुरी तरह गिरकर घायल हो गए।

हादसे के बाद आरोपी कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी भेजा गया। औपचारिकता के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस जांच में जुटी

सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बुजुर्ग महिला की नथ छीनी, बाइक से भागा बदमाश

टोंक। पुलिस थाना दूनी क्षेत्र के निवारिया गांव में मंगलवार सुबह एक बदमाश ने घर के आंगन में सो रही बुजुर्ग महिला की नाक से सोने की नथ छीन ली। नथ की कीमत करीब एक लाख दस हजार रुपए बताई गई है। वारदात सुबह करीब साढ़े चार बजे हुई। बदमाश बाइक से फरार हो गया। पूरी घटना पड़ोसी के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

पीड़िता गीता देवी कुछ दिन पहले अपने पीहर निवारिया आई थी। सोमवार रात वह अपने भाई प्रहलाद मीणा के घर के आंगन में सो रही थी। तभी एक अज्ञात बदमाश आंगन में घुसा। उसने महिला की नाक से 12 ग्राम सोने की नथ खींच ली। बदमाश ने नथ इतनी सफाई से खींची कि महिला को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। लेकिन महिला जाग गई और चिल्लाई।

चीख सुनकर पास ही सो रहा उसका भाई प्रहलाद भी जाग गया। उसने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन आरोपी ने उसे लात मारकर गिरा दिया और बाहर खड़ी बाइक पर सवार होकर अपने साथी के साथ भाग गया।

मनोहरपुरा दौसा हाइवे पर हादसा-खाटूश्यामजी के भक्तों को ट्रोले ने कुचला, 3 की मौके पर मौत

जयपुर। राजधानी से सटे मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे (ह॥-148) एक बार फिर मौत की पटरियों में तब्दील हो गया। रविवार सुबह गठवाड़ी मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर हालत में ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन घर से निकले तो लौटकर लाश बनकर आए।

हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे ट्रोले से भिड़ गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग बुरी तरह फंस गए। क्षत-विक्षत शव देखकर मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे।

हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस और हाईवे चेतक करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे। देरी से पहुंची पुलिस को देखकर गुस्साए ग्रामीणों ने लापरवाही पर नाराजगी जताई और मौके पर ही हंगामा कर दिया।

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर कार में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकाला। कुछ ने एंबुलेंस की व्यवस्था की, तो कुछ घायलों को संभालते रहे। इस मंजर को जिसने देखा उसकी आंखें नम हो गईं। किसी की बहन गई, किसी का भाई और किसी का बेटा ङ्क खाटूश्यामजी की राह पर निकले श्रद्धालु मौत की राह चले गए।

रायसर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज निम्स अस्पताल में जारी है।

सवालों के घेरे में हाईवे सुरक्षा

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं ङ्क हाईवे पर भारी वाहनों की रफ्तार पर कौन लगाम लगाएगा? क्यों हर हादसे के बाद भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है? और कब तक श्रद्धा की राह पर निकले लोग लाश बनकर लौटेंगे?

श्रद्धालुओं की यात्रा, अब श्रद्धांजलि में बदली

जो लोग सुबह उम्मीदों और भक्ति के साथ घर से निकले थे, शाम होते-होते उनके घरों में मातम छा गया। खाटूश्यामजी के दरबार तक पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं। अब परिवार वालों के पास बस उनकी यादें बची हैं और कुछ क्षत-विक्षत तस्वीरें।

यह कोई पहला हादसा नहीं... और शायद आखिरी भी नहीं

जब तक हाईवे पर रफ्तार पर लगाम नहीं लगेगी, सिस्टम की नींद नहीं खुलेगी, और श्रद्धा की यात्रा को सुरक्षित नहीं बनाया जाएगा - तब तक जयपुर-दौसा हाईवे पर मौत का खेल यूं ही जारी रहेगा। जो लौटकर नहीं आए, वो सिर्फ श्रद्धालु नहीं थे, किसी के बेटे, किसी की मां और किसी का सहारा थे...

प्रदेश भर से लापता 21 व्यक्तियों की पुलिस को है तलाश, गुमशुदा के बारे में कोई भी जानकारी होने पर तुरन्त करें सूचित

जयपुर। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर से लापता हुए व्यक्तियों की तलाश में लगातार सक्रिय है और इस महत्वपूर्ण कार्य में जनता से सहायता की उम्मीद करती है। हाल ही में, विभिन्न जिलों से कुल 21 व्यक्तियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन सभी की गुमशुदगी अलग-अलग तारीखों पर दर्ज की गई है।

गुमशुदा व्यक्तियों का विवरण

हनुमानगढ़ जिले से सर्वाधिक 17 व्यक्ति लापता हैं, जिनमें 5 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

पुरुष

1. नील कमल (22 वर्ष) पुत्र राजू हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 12, जोड़किया का निवासी है। उसका कद 5.6 फीट और रंग गोरा है।

2. बलराज (22 वर्ष) पुत्र लक्ष्मण गुप्ता, नोहर के वार्ड नंबर 23 का रहने वाला है।

3. लोकेश उर्फ अंकुश (25 वर्ष), हनुमानगढ़ टाउन के चाहुवाली का निवासी है। उसका कद 5.6 फीट और रंग गेहुंआ है।

4. बुधराम (28 वर्ष) पुत्र मिठु सिंह बाजीगर, हनुमानगढ़ टाउन के प्रेम नगर का निवासी है।

5. मनीराम (58 वर्ष) पुत्र मनफूल, रावतसर के चक 26 आरडब्ल्यूडी गंधोली का निवासी है। उसका कद 5.6 फीट और रंग गोरा है और वह सफेद कमीज पहने हुए था।

महिलाएं

1. पूजा (18 वर्ष) पुत्री ओमप्रकाश, हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 58, सुरेशिया की निवासी है। उसका कद 5 फीट और रंग गोरा है।

2. यशोदा कंवर (25 वर्ष) पुत्री किरण सिंह राजपूत, हनुमानगढ़ जंक्शन की वार्ड नंबर 17, दिल्लो कॉलोनी की निवासी है। उसका कद 5 फीट और रंग सांवला है।

3. कविता (22 वर्ष) पुत्री छिन्द्रपाल सिंह, पीलीबंगा के वार्ड नंबर 13, अमरपुरा ढाणी, 19 पीबीएन बी की निवासी है। उसका कद 5 फीट और रंग गेहुंआ है, और वह पीले रंग का सलवार सूट पहने हुए थी।

4. रेखा (28 वर्ष) पुत्री उतरेश ओड, सदर थाना क्षेत्र के जंडावाली की निवासी है। उसका कद 5.3 फीट और रंग गेहुंआ है।

5. ज्योति (22 वर्ष) पत्नी अमनदीप जाट, भिरानी के झिलोदा की निवासी है। उसका रंग गेहुंआ है।

6. कांता (30 वर्ष) पुत्री सोहन लाल मेघवाल, फेफाना की निवासी है। उसका रंग गेहुंआ है।

7. रेशमा (24 वर्ष) पुत्री कृष्ण लाल सुथार, पल्लू के पूरबसर की निवासी है। उसका कद 5 फीट और रंग गेहुंआ है।

8. समेस्ता (18 वर्ष) पुत्री रोहताश धाणक, गोगामेड़ी के तेलयान की ढाणी, खचवाना की निवासी है। उसका रंग गोरा है।

9. सोनू (25 वर्ष) पत्नी रणजीत जलंधरा, तलवाड़ा के चक 6 डीबीएल डबलीखुर्द की निवासी है। उसका कद 5 फीट और रंग गेहुंआ है।

10. मैना (20 वर्ष) पुत्री कालुराम मेघवाल, तलवाड़ा की निवासी है। उसका कद 5.3 फीट और रंग गेहुंआ है।

11. मनीषा (18 वर्ष) पुत्री करण सिंह मेघवाल, भिरानी के झांसल की निवासी है। उसका रंग गेहुंआ है।

12. सतवीर कौर (39 वर्ष) पत्नी धन्न सिंह जटसिख, हनुमानगढ़ टाउन की निवासी है। उसका कद 5.6 फीट और रंग सांवला है।

अन्य जिलों से लापता व्यक्ति

जैसलमेर जिले से

1. रूपाराम (14 वर्ष), राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, जैसलमेर कोतवाली से लापता है। उसका रंग गोरा है और उसके दोनों हाथों के अंगूठे व अंगुलियां जली हुई हैं।

अजमेर जिले से

1. महेंद्र सिंह (40 वर्ष) पुत्र प्रेम सिंह रावत, सीकर जिले के खाटूश्याम क्षेत्र से लापता है। वह अजमेर के गगवाना थाना क्षेत्र के लाडपुरा का निवासी है। उसका कद 5.6 फीट और रंग गेहुंआ है। वह सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए था।

दौसा जिले से

1.कपिल (37 वर्ष) पुत्र रामाश्रय, मेहंदीपुर बालाजी का निवासी है। उसका कद 5.7 फीट और रंग गेहुंआ है। वह सफेद शर्ट और काला पायजामा पहने हुए था।

खैरथल तिजारा जिले से

1. मोनिका (17-18 वर्ष) पुत्री नवल सिंह, तत्तारपुर थाना क्षेत्र के नंगली ओझा की निवासी है। उसका कद 5.2 फीट और रंग गेहुंआ है। वह सूट सलवार पहने हुई थी।

राजस्थान पुलिस आम जनता से विनम्र निवेदन करती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो वे तुरंत संबंधित जिला कंट्रोल रूम या संबंधित पुलिस थाने में सूचित करें। आपकी थोड़ी सी जानकारी किसी परिवार के लिए बड़ी उम्मीद बन सकती है। पुलिस प्रशासन इस अभियान में आपकी सक्रिय भागीदारी की सराहना करता है।

(पर्यावरण-चिंतन) अंधड़, बारिश और चेतावनीः बदलता मौसम, बिगड़ता संतुलन

मौसम विभाग ने इस बार के तूफान के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के संगम को कारण बताया है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ नवंबर से अप्रैल के बीच सक्रिय रहता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मई-जून में भी सक्रिय रहने लगा है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि का संकेत है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि पारंपरिक मौसम चक्रों में अब स्थायित्व नहीं रहा और मौसम की गतिविधियां अधिक अनियमित और अस्थिर होती जा रही हैं।

(लेखक-योगेश गोयल)

24-25 मई की रात उत्तर भारत के लिए एक बार फिर ऐसी रात बनकर आई, जिसने न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत को झकझोरकर रख दिया। इस प्रचंड मौसमीय तांडव ने न केवल जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया बल्कि एक बार फिर यह संकेत दे दिया कि अब मौसम चक्रों में स्थायित्व नहीं रहा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे सिर पर मंडरा रहा है। एक ओर जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी ओर भीषण बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। मई महीने में जब उत्तर भारत 44-45 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है, ऐसे समय में अचानक ऐसे तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसे दृश्य आमतौर पर मानसून के चरम काल में भी दुर्लभ होते हैं।

हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस तूफान से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था परंतु तूफान की तीव्रता और व्यापक प्रभाव ने पारंपरिक मौसमी पूर्वानुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। रविवार की देर रात तेज हवाओं ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से तेजी से बढ़ते तूफानी बादल महज कुछ ही घंटों में दिल्ली-एनसीआर की ओर आ गए। आसमान में अचानक तेज बिजली चमकने लगी, फिर गरज के साथ बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते स्थिति एक शक्तिशाली तूफान में बदल गई। हवा की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, ट्रैफिक सिग्नल गिर गए, बिजली के खंभे झुक गए और कई वाहनों को क्षति पहुंची। आईएमडी के अनुसार, इस दौरान हवा की गति 60 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच गई थी और कुछ स्थानों पर तो यह इससे भी अधिक रिकॉर्ड की गई।

केवल दिल्ली ही नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के प्रमुख शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। गुरुग्राम में तेज हवा के कारण कई जगहों पर निर्माणाधीन साइटों की छतें उड़ गईं जबकि नोएडा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की क्रेन गिरने से दो लोग घायल हो गए। उत्तर भारत के अन्य भागों, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान में भी यह तूफान तबाही लेकर आया। जगह-जगह सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, जिससे कई जगहों पर सड़कों का संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने की घटना भी सामने आई, जहां सात वाहन बह गए और कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। पंजाब में वर्षाजनित हादसों में कुछ लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई। खेतों में काम कर रहे किसान तेज आंधी की चपेट में आ गए। इससे पहले 21 मई को भी शाम के समय अचानक दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदल गया था और अचानक बदले मौसम के बीच भीषण आंधी-तूफान और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई थी। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि नोएडा, गाजियाबाद सहित देश के कई राज्यों में लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। उस दौरान हुए हादसों में 7 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि देशभर में करीब 26 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी।

इस साल मई महीने की शुरुआत ही इसी प्रकार के अप्रत्याशित मौसमी बदलावों के साथ हुई थी। 2 मई की सुबह दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और तूफान जैसी स्थिति बनी थी। दिल्ली में उस दिन 78 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश के साथ भारी नुकसान हुआ था। पेड़ उखड़ गए थे, बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि उस समय भी लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी लेकिन इस बार मई के अंत में आया यह तूफान कहीं अधिक गंभीर और व्यापक प्रभाव वाला था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब केवल सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन के गहरे संकेत हैं। दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन अब मौसम चक्रों को अस्थिर कर रहा है। 'शहरी हीट आइलैंड' प्रभाव के चलते रात के तापमान में गिरावट नहीं होती और वातावरण की ऊष्मा बढ़ती जाती है। कंक्रीट, एस्फाल्ट और अन्य मानव निर्मित सतहें सूरज की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और धीरे-धीरे उसे छोड़ती हैं, जिससे रात में भी वातावरण गर्म बना रहता है। 2 मई की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सामान्यतः ऐसी बारिश के बाद तापमान 18-20 डिग्री तक गिर जाता है। मौसम विभाग ने इस बार के तूफान के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के संगम को कारण बताया है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ नवंबर से अप्रैल के बीच सक्रिय रहता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मई-जून में भी सक्रिय रहने लगा है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि का संकेत है। यह संकेत स्पष्ट करता है कि पारंपरिक मौसम चक्रों में अब स्थायित्व नहीं रहा और मौसम की गतिविधियां अधिक अनियमित और अस्थिर होती जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं जब पश्चिमी विक्षोभ से टकराती हैं तो वह एक संगठित मौसमी प्रणाली का निर्माण करती हैं, जिससे उत्तर भारत में भारी वर्षा, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होती है। यह आमतौर पर मानसून के मध्य चरणों में होता है लेकिन मई की शुरूआत में या मई के अंतिम सप्ताह में इस प्रकार की घटनाएं असामान्य हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि मौसमी प्रवृत्तियों की दिशा अब बदल रही है।

कृषि क्षेत्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस समय अधिकांश क्षेत्रों में मूंग, सब्जियां, तरबूज, खरबूजा और अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती होती हैं। तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश इन फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। बिहार, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने फलों और सब्जियों के खराब होने की शिकायत की है। इससे न केवल किसानों की आमदनी प्रभावित होती है बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा बाजारों में कीमतों पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमालय क्षेत्र में भी गहराई से महसूस किया जा रहा है। बर्फबारी का स्तर 23 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे हिमालय की नदियों पर निर्भर करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम अब पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित और अस्थिर हो गया है। असामान्य तूफान, बेमौसम बारिश और अचानक तापमान में बदलाव, यह सभी इस बात के संकेत हैं कि जलवायु अब अपने पुराने स्वरूप से हट चुकी है।

वर्तमान स्थिति में सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और आम नागरिकों के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। अब समय आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक बहस का विषय न मानें बल्कि इसे सार्वजनिक नीति और व्यक्तिगत जीवनशैली में भी प्राथमिकता दें। भारत को अब मौसम विज्ञान, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा नीति और शहरी नियोजन को आपस में जोड़ते हुए एक समग्र रणनीति बनानी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी अपनी रणनीतियों को अद्यतन करना होगा। अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु विशेषताओं के अनुसार अलग योजनाएं बनानी होंगी। दिल्ली-एनसीआर जैसे घने शहरी क्षेत्रों के लिए अलग मॉड्यूल हो जबकि हिमालयी क्षेत्रों के लिए भूस्खलन, बाढ़ और बर्फबारी पर केंद्रित योजनाएं हों। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए मौसम अनुकूल बीमा योजनाएं, सटीक पूर्वानुमान सेवाएं और प्राकृतिक आपदाओं से पहले सतर्कता की विश्वसनीय प्रणाली विकसित करनी होगी।

बहरहाल, दिल्ली और उत्तर भारत में अचानक और तीव्र रूप से बदलता मौसम अब कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं रह गया है बल्कि यह एक चेतावनी है कि यदि हम समय रहते नहीं चेते तो यह बदलाव हमें और अधिक विनाशकारी परिस्थितियों की ओर ले जा सकता है। यह समय है जब नीति निर्धारक, वैज्ञानिक और आमजन एकजुट होकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान निकालें। 24-25 मई की रात उत्तर भारत में आया तूफान न केवल भौतिक रूप से तबाही का प्रतीक था बल्कि यह जलवायु संकट की उस गंभीरता का द्योतक भी था, जिससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं। यदि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो इससे न केवल हमारी जीवनशैली प्रभावित होगी बल्कि भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, तैयारी करनी होगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा, तभी हम सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलों के जानकार और बहुचर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के लेखक हैं)

संपादकीय

मनरेगा को ठेंगा

श्रमिकों को घर के पास जीविका उपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई मनरेगा से जुड़ी धांधलियां अकसर उजागर होती रहती हैं। ताजा घटनाक्रम में ठेकेदारों व निहित स्वार्थी तत्वों की सांठगांठ को ऑनलाइन भुगतान के जरिये बेनकाब किया गया, जिसमें लाखों फर्जी श्रमिकों को भुगतान के मामले उजागर हुए। निश्चित रूप से ये घटनाएं हमारे समाज में येन-केन-प्रकारेण धन अर्जन की लालसा को ही उजागर करती हैं। साथ ही नैतिक मूल्यों के पतन की गाथा भी कहती हैं। ऐसे ही पंजाब के गुरदासपुर के गाजीकोट गांव में उजागर हुआ कार्टून घोटाला एक हास्यास्पद, लेकिन बेहद परेशान करने वाला उदाहरण है कि भ्रष्टाचार के लिये किस हद तक गिरा जा सकता है। कथित तौर पर पंचायत सदस्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत मजदूरों की उपस्थिति को फर्जी ढंग से दर्शाने के लिये एक सरकारी स्कूल के गेट पर बनाए गए कार्टूनों का सहारा लिया। इन चित्रों के साथ लाभार्थियों की तसवीरें मजदूरी के सबूत के तौर पर अपलोड की गई। विडंबना देखिए कि उस काम के लिए भुगतान लिया गया जो कभी किया ही नहीं गया था। दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक योजना के तहत स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग्स बनायी थी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया जा सके। लेकिन शातिर लोगों ने उसका दुरुपयोग मनरेगा में घोटाले को अंजाम देने के लिए किया। निश्चय ही यह हमारे समाज में कुशासन, नैतिक पतन और तकनीकी खामियों की घातक जुगलबंदी को दर्शाता है। इस घोटाले का एक बेशर्म पहलू यह भी था कि कथित तौर पर पंचायत अधिकारियों के करीबी दो भाइयों को कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह काल्पनिक काम के लिये बेशर्मी से भुगतान कर दिया गया। यही वजह है कि मनरेगा के तहत वित्तीय आवंटन व योजना के क्रियान्वयन को व्यावहारिक बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य व अदृश्य बेरोजगारी दूर करने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है। निस्संदेह, लंबे अरसे से मनरेगा के तहत मजदूरी देने में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। यह केवल पंजाब के गुरदासपुर का मामला ही नहीं है, हाल के वर्षों में पूरे देश में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले उजागर होते रहे हैं। कुछ दिन पहले, गुजरात में एक राज्य मंत्री के बेटों से जुड़े 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में फर्जी प्रोजेक्ट और अन्य धांधलियां सामने आई थीं। मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान किया गया। कुछ माह पूर्व कर्नाटक में, पुरुष श्रमिकों ने महिला जॉब कार्डधारकों का रूप धारण करने के लिये साड़ी पहनी थी। ये उदाहरण ग्रामीण आजीविका और सम्मान को बनाये रखने के लिये बनायी योजना का मजाक उड़ाने वाले हैं। दरअसल, ऐसे घोटालों का उजागर होना अंततः कल्याणकारी कार्यक्रमों में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। सही मायनों में ऐसी धांधलियों से वास्तविक लाभार्थियों के हितों को नुकसान पहुंचता है।

परीक्षा प्रणाली या सामाजिक भ्रमजाल?

(लेखिका - सोनम लववंशी)

शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक 'अंक-उद्योग' में तब्दील हो चुकी है, जहां ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अंक-दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक साजिशन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कृत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संचालित हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138 केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं, जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही 'अंकवीर' छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, जेईई या नीट में पहुंचते हैं, तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटंत विद्या, तयशुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है, जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं। यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रौशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता-पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

यहां तक की कोचिंग टाउन बन चुके शहर कोटा, दिल्ली, पटना, प्रयागराज और इंदौर इस अंक-उद्योग की सबसे बड़ी मिसाल हैं। यहां छोटे-छोटे बच्चों से लेकर स्नातक विद्यार्थी तक 'रैंक मशीन' बनने के लिए दिन-रात खप रहे हैं। यह एक सामाजिक दबाव का परिणाम है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में डॉक्टर-इंजीनियर बनने की लीक पर चलता है। वहीं दक्षिण भारत में शिक्षा के विविध विकल्पों, व्यावसायिक दक्षता और कौशल विकास को भी उतना ही महत्व मिलता है। यह सोच का फर्क है, जो वहां के छात्रों को तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में मजबूत बनाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अंक-उद्योग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह छात्रों के भीतर सोचने, सवाल उठाने और नवाचार की प्रवृत्ति को कुचल देता है। शिक्षा का उद्देश्य विवेक, तर्क और संदेह की भावना का विकास था, पर अब यह केवल स्मृति और दोहराव पर आधारित हो गया है। मीडिया में टॉपर बच्चों के साक्षात्कार इस मानसिकता को और पुष्ट करते हैं, जहां दिन में 16 घंटे पढ़ना, दस साल के पेपर रटना और कई-कई किताबें घोंटना ही सफलता का मंत्र बताया जाता है। यह विचारणीय है कि क्या वास्तव में यही शिक्षा है?

इस समस्या का समाधान केवल परीक्षा प्रणाली बदल देने से नहीं होगा। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक शिक्षा का यह विकृत रूप बना रहेगा। जब तक अभिभावक अंक को ही सफलता की कसौटी मानते रहेंगे, स्कूलों और शिक्षकों की प्राथमिकता भी वहीं रहेगी। ज़रूरत है एक नई शैक्षणिक संस्कृति की जहां असफलता को अवसर माना जाए, बच्चों की विविधता को अपनाया जाए और उन्हें आत्मविश्लेषण और आत्म-अनुशासन के मार्ग पर प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें की हैं, परंतु इन्हें जमीन पर लागू करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। अब समय है कि हम स्कूलों को रैंक उत्पादक मशीनों से बाहर निकालें। अभिभावकों को समझना होगा कि उनका बच्चा कोई अंकों का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि एक सोचने, समझने और विकसित होने वाली मनुष्य-प्रवृत्ति है। शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम पूरा कराने से आगे बढ़कर बच्चों में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और सामाजिक चेतना जगानी होगी। जब शिक्षा फिर से इंसान गढ़ने लगेगी, तभी यह राष्ट्र को सही अर्थों में शिक्षित बना पाएगी।

(स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी)

(यह ले खिका के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

(चिंतन-मनन)

चिंतन मनन

मूर्तिकार का सपना

एक मूर्तिकार ने एक रात विचित्र स्वप्न देखा। वह किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठा लिया फिर उसे सामने रखा और औजारों के थैले से छेनी-हथौड़ी निकालकर उसे तराशने के लिए जैसे ही पहली चोट की, पत्थर जोर से चिल्ला पड़ा- मुझे मत मारो। दूसरी बार वह रोने लगा। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पसंद का एक अन्य टुकड़ा उठाया और उसे तराशने लगा। वह टुकड़ा चुपचाप वार सहता गया और देखते ही देखते उसमें से एक एक देवी की मूर्ती उभर आई। मूर्ति वहीं पेड़ के नीचे रख वह आगे चला गया। फिर कुछ समय बाद वह उसी पुराने रास्ते से गुजरा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि उस मूर्ति की पूजा-अर्चना हो रही है, जो उसने बनाई थी। भीड़ लगी है, भजन आरती हो रही है, भक्तों की पंक्तियां लगी हैं। जब उसके दर्शन का समय आया, तो पास आकर उसने देखा कि उसकी बनाई मूर्ति के सामने न जाने क्या-क्या रखा है। जो पत्थर का पहला टुकड़ा उसने, उसके रोने चिल्लाने पर फेंक दिया था वह भी एक ओर पड़ा है और लोग उसके सिर पर नारियल फोड़ -फोड़ कर देवी की मूर्ति पर चढ़ा रहे है। तभी मूर्तिकार की नींद टूट गई। वह सपने के बारे में सोचने लगा।

उसने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं, उनका जीवन बन जाता है। विश्व उनका सत्कार करता है। पर जो डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं वे बाद में जीवन भर कष्ट झेलते हैं, उनका सत्कार कोई नहीं करता।

विचार मंथन

हिन्दुस्तानी छात्रों से अमेरिका को अरबों की कमाई

(लेखक- सनत जैन)

अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसमें लगभग 60 फीसदी भारतीय छात्र होते हैं। इन छात्रों द्वारा लाखों रुपए की फीस अमेरिका के शिक्षण संस्थानों को दी जाती है। विदेशी छात्रों की फीस से अमेरिका के शिक्षण संस्थानों को लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष की कमाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने विदेशियों के बारे में जो राय बनाई है। उसके कारण अमेरिका का शैक्षणिक जगत समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है। अमेरिका के शिक्षण संस्थानों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की टेडी नजर है। ट्रम्प के कारण अमेरिका को आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सारी दुनिया में नाम है। यहां पर एडमिशन लेने के लिए दुनिया के सभी देशों से बच्चे यहां आकर पढ़ना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी। हालांकि अमेरिका के न्यायालय ने ट्रंप के आदेश को रद्द कर दिया है, लेकिन यह खतरा अभी टला नहीं है। ट्रंप सरकार का रवैया विदेशियों के लिए बहुत आक्रामक और अपमानजनक है। ट्रंप के रूख और फैसलों को देखते हुए, अब सारी दुनिया के देशों से अमेरिका में पढ़ने के लिए जो छात्र आते थे। उनकी संख्या में इस साल भारी गिरावट आई है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों के साथ जिस तरह की प्रताड़ना की जा रही है। छात्रों को अनाप-शनाप आरोपों में अमेरिका से निष्कासित किया जा रहा है। उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भारत सहित दुनिया के देशों में हुई है। ट्रंप सरकार का कहना है, अमेरिकी के विश्वविद्यालयों में यहूदी विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं। ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई को अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अमेरिका में यह आजादी अब खत्म होती दिखने लगी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा छात्र भारत से पढ़ने के लिए जाते हैं। अमेरिका की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वह भारतीय विदेशी छात्रों के बल पर चल रही हैं। कई विश्वविद्यालय में 24 फ़ीसदी से लेकर 51 फीसदी तक विदेशी छात्र महंगी फीस देकर पढ़ रहे है। यह विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के बल पर चल रहे हैं। अमेरिकी छात्रों की तुलना में विदेशी छात्रों से ज्यादा फीस वसूल की जाती है। पिछले 4 महीने में ट्रंप प्रशासन द्वारा जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया गया है। विदेशी छात्रों पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर अमेरिका की साख दुनिया भर के देशों में अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब हुई है। यदि यही हाल रहा तो अमेरिका के विश्वविद्यालय आर्थिक संकट के कारण स्वयं बंद हो जाएंगे। अमेरिकी सरकार ने विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान में कटौती की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का तो पूरा अनुदान ही बंद कर दिया है। अमेरिका के सारे विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के बल पर चल रहे थे। यदि विदेशी छात्र नहीं आएंगे, तो अमेरिका के शिक्षण संस्थान बंद होंगे। इसके साथ-साथ अमेरिका के शिक्षण संस्थानों को लगभग 3.65 लाख करोड रुपए जो फीस के रूप में एकत्रित होते थे। इससे दो गुना ज्यादा राशि विदेशी छात्रों द्वारा अमेरिका में खर्च की जाती थी, अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय माना जा रहा है। अमेरिका इस समय सबसे बड़े कर्ज के दबाव से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय पर भारत में शिक्षण संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार को स्वायता देने की जरूरत है। भारत में पढ़ाई और रिसर्च के लिये यदि अच्छे संस्थान विकसित किए जाते हैं। ऐसी दशा में भारतीय छात्रों को अमेरिका और यूरोप के देशों में इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने

के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भारत के लिए एक अवसर है, अमेरिका में अभी जो चल रहा है, उसका लाभ भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये किया जाये। ताकि भारतीय बच्चों का शिक्षा के लिये विदेश जाना कम हो। इससे भारत को विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वहीं भारतीय अर्थ- व्यवस्था बेहतर बनाया जा सकेगा।

फिर डरा रहा कोरोना, महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा मौतें, देश में 1045 हुए एक्टिव केस

नई दिल्ली।

देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर डराना शुरु कर दिया है। लोगों के मन डर है कि कहीं लॉकडाउन की स्थिति न बन जाए। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है फिर भी जिस गति से कोरोना के केस आ रहे है वो डराते दिखाई दे रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में हैं। वहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से आठ की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा पांच मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर डॉ राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वैरिएंट मिले हैं। इनमें एलएफ.7, एक्सएफजी, जेएन.1 और एनबी.1.8.1 वैरिएंट शामिल हैं।

इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में दो लोगों की कोविड से मौत हुई है। भारत में मिले कोविड-19 के 4 नए वैरिएंट भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में चार नए वैरिएंट मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि, निगरानी में रखे गए वैरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यह वैरिएंट मिलता है।

24 घंटे में कोरोना से 3 की मौत

24 घंटे में कोरोना से 3 मौतें जयपुर में सोमवार को कोरोना के दो मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था। उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उसे पहले से ही टीबी की बीमारी थी। वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे में एक

कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई (रविवार) को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था।

समीकरणों के बदलाव की आहटः राज्यसभा में बढ़ सकती हैं विपक्ष की सीटें

नई दिल्ली।

अगले माह 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होना है तो वहीं असम की दो सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। ये सीटों राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रही हैं। तमिलनाडु के 6 सदस्य जुलाई में रिटायर होंगे, जबकि असम के दो सदस्यों का जून महीने में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु में जिन 6 सीटों पर इलेक्श होना है, उनमें से तीन पर अब तक डीएमके के सदस्य थे। इसके अलावा तीन सीटों पर पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के मेंबर सांसद थे। इससे संभावना है कि विपक्ष की सीटें बढ़ सकती हैं। फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा का जो समीकरण है, उसके हिसाब से डीएमके का नंबर तीन से 4 हो सकता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस के साथ सहमति बनी तो फिर डीएमके एक सीट उसे भी दे सकती है। ऐसा होने पर भी विपक्षी गठबंधन के खाते में ही एक और सीट जाएगी। इसी तरह असम के आंकड़ों को देखते हुए भी विपक्ष के खाते में एक सीट का इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं, वे भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं। लेकिन विधानसभा का जो समीकरण है, उस लिहाज से चुनाव की स्थिति में एक सीट भाजपा को मिलेगी तो वहीं एक अन्य सीट कांग्रेस या फिर उसके सहयोगी को मिल सकती है।इस तरह चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें 91 हो सकती हैं, जो अभी 89 ही हैं। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 हैं, वे घटकर 126 ही रह सकती हैं। बता दें कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनावी हार के बाद विपक्ष के लिए यह राहत भरी खबर होगी। दरअसल कई राज्यों के चुनावों में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मात झेलनी पड़ी है। झारखंड को इसमें अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, जहां झामुमो की लीडरशिप में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी है।

जगन्नाथ मंदिर से जुड़े श्री जगन्नाथ धाम, श्रीक्षेत्र जैसे कई शब्दों का होगा पेटेंट

भुवनेश्वर।

पश्चिम बंगाल के दीघा मंदिर को धाम नाम देने को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) ने सोमवार को ओडिशा में 12वीं शताब्दी के मंदिर से जुड़े कुछ शब्दों और 'लोगो' का पेटेंट कराने का फैसला किया। जल्द ही महाप्रसाद (भोग), श्रीमंदिर (मंदिर), श्री जगन्नाथ धाम (स्थान), श्रीक्षेत्र (स्थान) और पुरुषोत्तम धाम (स्थान) जैसे शब्दों के पेटेंट के लिए आवेदन करेगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को एसजेटीएमसी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बैठक में, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीएमसी) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढी, पुरी जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वैन, पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल और पदेन सदस्य शामिल हुए। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक पाढी ने संवाददाताओं से कहा, एसजेटीए जल्द ही महाप्रसाद (भोग), श्रीमंदिर (मंदिर), श्री जगन्नाथ धाम (स्थान), श्रीक्षेत्र (स्थान) और पुरुषोत्तम धाम (स्थान) जैसे शब्दों के पेटेंट के लिए आवेदन करेगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को एसजेटीएमसी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पाढी ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर से संबंधित विशिष्ट शब्दों और 'लोगो'का पेटेंट कराना पुरी मंदिर की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान की रक्षा के लिए एक कानूनी उपाय के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, इससे 12वीं शताब्दी की मूल आध्यात्मिक पहचान के दुरुपयोग और इसकी शब्दावली के अनधिकृत उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।जगन्नाथ धाम शब्द के कथित दुरुपयोग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चल रहे विवाद के बारे में पाढी ने कहा कि इस मामले का हल राज्य

सरकारों द्वारा किया जाएगा। देब ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार दीघा स्थित अपने मंदिर के लिए जगन्नाथ धाम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह हिंदू धर्मग्रंथों और भगवान जगन्नाथ की सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ है। गजपति महाराज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मुद्दे का हल दो राज्य सरकारों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए। तभी इसका सही समाधान हो सकेगा।

पहलगाम के आतंकी कहां गए? क्या गुजरात या दाहोद में छिपाया है?

शिवसेना सांसद राउत ने कहा- गृहमंत्री शाह को प्रायश्चित करना चाहिए

नई दिल्ली।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था।

सेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और सीमा पार के पंजाब प्रांत में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।

इस ऑपरेशन को लेकर अब सियासत होने लगी है। केंद्र में एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी इस ऑपरेशन की सफलता का जश्न मना रही है, देशभर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं, अब विपक्षी दल इस ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को विफलता बताते हुए कहा कि यह राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते।

उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमारे 26 बेगुनाह लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत पड़ी क्योंकि पहलगाम हमले में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। शिवसेना सांसद राउत ने कहा कि अमित शाह को इसका प्रायश्चित करना चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राउत ने सरकार से सवाल किया कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी कहां गए? क्या गुजरात या दाहोद में उन आतंकियों को छिपाया है?

राउत के बाद यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इमरान मसूद ने सवालिया लहजे में कहा कि पहलगाम के आतंकी कहां गए? उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई? उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि पहलगाम के आतंकी कहां गए। मसूद ने कहा कि सेना ने गोले तो दाग दिए थे।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराना था, लेकिन सेना को पीएम मोदी ने रोक दिया। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताया था। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब चार दिन तक चले युद्ध जैसे हालात के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ में बात हुई।

अब भारत नहीं आ पाएंगे पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की शुरु होगी आवाजाही

नई दिल्ली।

भारत सरकार ने न्यू अफगान वीजा मॉड्यूल के तहत जो सेवा शुरू की है, उसके अनुसार ऐसे लोगों को ही वीजा मिलेगा, जिन्हें किसी तरह का इलाज कराना हो या फिर मरीज की तीमारदारी करनी हो।

वहीं छात्रों, कारोबारियों, मेडिकल अटेंडेंट, यूएन डिप्लोमैट वीजा पर आने वाले लोगों को भी एंट्री दी जाएगी। इन वीजा के आवेदनों पर हर मामले को लेकर अलग-अलग फैसला लिया जाएगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के लोगों की एंट्री पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है।

वीजा सेवाएं ठप कर दी गई हैं। इस बीच तालिबान से भारत के रिश्तों में सुधार को देखते हुए अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजा सेवाओं को शुरू किया गया है।

बीते माह विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी से बात की थी। वहीं तालिबान शासन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी और कहा था कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भी साझेदारी है।

वहीं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह कॉरिडोर भारत से लेकर ईरान, रूस होते हुए यूरोप को जोड़ने वाला है। इस तरह दो अहम प्रोजेक्ट्स में दोनों देश साथ हैं और पाकिस्तान के साथ दोनों के ही संबंध सहज नहीं हैं।

अफगानिस्तान के लोगों को वीजा आवेदन करने के लिए मौके की एक तस्वीर, पासपोर्ट की डिटेल्स और एक अन्य आईडी कार्ड पोर्टल पर सबमिट करना होगा।

यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ महीनों में तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हुए हैं। तालिबान ने भारत को भरोसा दिया है कि उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान से उसके रिश्ते खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आतंकियों और डूरंड लाइन को लेकर सहज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत के साथ संबंध सुधार के अपने मायने हैं। भारत ने अफगानियों के लिए वीजा सेवा शुरू करके इसका संदेश भी दिया है।

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान ने सैन्य ठिकानों के लोकेशन भेजे

नई दिल्ली।

जासूसी के आरोप में पकड़ा गया सीआरपीएफ का जवान हमले से ठीक पहले तक पहलगाम में ही तैनात था। 22 अप्रैल को हुए हमले से 6 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। आरोपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोती राम जाट को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।मोतीराम पहलगाम में सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय सूचनाएं दे रहा था। वह 2023 से ही पैसों के बदले देश के साथ गद्दारी कर रहा था। उसने पाकिस्तान को भारतीय सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल जानकारी, मूवमेंट के तरीके और अहम सैन्य ठिकानों का लोकेशन भेज चुका था।

गिरफ्तारी के बाद जवान को बर्खास्त कर दिया गया है।

एनआईए के अधिकारी जासूसी के आरोपी जवान से पूछताछ में जुटे हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह क्या-क्या गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दे चुका था और पाकिस्तान में किन-किन लोगों से संपर्क में था। वह कैसे पाकिस्तान का मोहरा बना यह भी पता लगाया जा रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को धर्म पूछकर मार डाला था। मृतकों में अधिकतर हिंदू थे। सीआरपीएफ के एक बयान के अनुसार जाट

केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से आया। सीआरपीएफ की ओर से बताया गया कि जाट को आगे की जांच के लिए एनआईए के हवाले कर दिया गया है। बयान में कहा गया है, इसके साथ ही, सीआरपीएफ नियमों के साथ संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस व्यक्ति को 21 मई से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।आरोपी को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया गया।

भारत करांची बंदरगाह पर हमले के लिए था तैयार, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया पाक

भारतीय वायुसेना ने कई एयरबेस को कर दिया था तबाह

नई दिल्ली।

मई की रात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट विश्व मंच तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन बनयान अल-मरसूस' नामक सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, लेकिन यह महज आठ घंटे में ही धराशायी हो गई। जवाबी कार्रवाई में भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाही कर दिया। रातोंरात भारतीय राफेल विमानों से मिसाइलें और एसयू-30 एमकेआई विमानों से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें दागी गईं। हमलों में चकलाल में नूर खान एयरबेस, जैकोबाबाद और भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान की उत्तरी एयर कमांड के कमांड-कंट्रोल नेटवर्क का हिस्सा था और पहले ही हमले में ध्वस्त हो गया।

मीडिया रिपोर्ट में वायुसेना के पास मौजूद सबूतों के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के एक सी-130जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक जेएफ-17, और दो एफ-16 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। भारतीय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो आदमपुर एयरबेस पर तैनात था, उसने इस ऑपरेशन में 11 बार दुश्मन के विमानों को रोका। इसने 315 किमी दूर पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे साब-2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी निशाना बनाकर गिरा दिया। 10 मई को भारत ने लाहौर में तैनात चीनी एलवॉय-80 एयर डिफेंस सिस्टम को हारपेज कामिकेज़ ड्रोन से तबाह कर दिया। इसके अलावा करांची के मलीर इलाके में तैनात एयक्यू-9 को भी भारत की मिसाइल ने नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने 10 मई को अपने ऑपरेशन की शुरुआत की थी और दावा किया था कि वह 48 घंटे में भारत के एयरबेस तबाह कर देगा, लेकिन भारतीय सेना के सटीक और तीव्र प्रहार से पाकिस्तान की योजना पस्त पढ़ गई। स्थिति जब हाथ से निकलने लगी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीजफायर की अपील की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना करांची बंदरगाह पर हमले के लिए तैयार थी और उसका बेड़ा मकरान तट से महज 260 मील दूर था। पाकिस्तान ने चेतावनी दी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। दोपहर तक पाकिस्तान ने युद्धविराम की आधिकारिक गुहार लगाई।

आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ का दिया रिकॉर्ड डिविडेंड

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। अमेरिकी डॉलर की बिक्री और प्रतिभूतियों से हुई ब्याज आय की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.7 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक डिविडेंड देने की घोषणा की है।

विश्लेषकों ने कहा कि इससे सरकार को अमेरिकी टैरिफ और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण रक्षा पर खर्च में वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के वर्षों से आरबीआई सरकार को अधिक से अधिक

अधिशेष हस्तांतरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बावजूद इस बार अधिशेष हस्तांतरण बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तुलना में केंद्रीय बैंक ने अधिक डिविडेंड दिया है। हालांकि, यह बाजार उम्मीदों से कम है। बाजार आरबीआई से सरकार को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के डिविडेंड की उम्मीद कर रहा था।

संक्षिप्त समाचार

आगरा में छत्रपति शिवाजी का स्मारक यूपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएंगे

आगरा।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी का स्मारक यूपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएंगे। यूपी सरकार भूमि खरीदेगी और महाराष्ट्र सरकार स्मारक का निर्माण कराएगी। भूमि विवाद कोर्ट में विचाराधीन होने के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट में पैसा जमा कराएगी। ट्रस्ट या व्यक्ति जिसके पक्ष में फैसला होगा, वह पैसा उठा लेगा। पर्यटन मंत्री विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने यहां आए थे। शिल्पग्राम के समीप छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम का काम शुरू नहीं होने पर उन्होंने कहा कि 31 मई से काम शुरू हो जाएगा। प्री-कॉस्ट तकनीकी से काम होने से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने आगरा व मथुरा के गोवर्धन में हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू नहीं होने पर कहा कि कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है। कुछ कारणों से उड़ान शुरू नहीं हो सकी थी। शीघ्र ही दोनों शहरों में उड़ान शुरू की जाएंगी।

तुर्की की कंपनी को हाईकोर्ट से स्टे

मुंबई।

भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में सैनिक कार्रवाई में भाग लिया। भारतीय सेना को काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद भारत सरकार और कंपनियों ने तुर्की से अपने कारोबारी संबंध खत्म करने का निर्णय लिया था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में हैंडलिंग और सर्विस देने का काम तुर्की की फर्म मायल कर रही थी। इसका अनुबंध सेलेबी द्वारा खत्म किया गया। इस आदेश के खिलाफ तुर्की की कंपनी मायल को बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टे मिल गया है। अदालत ने कहा है कि जब तक याचिका में कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। तब तक कोई नए टेंडर जारी नहीं किए जाएं। जब तक अदालत में मामला लंबित रहेगा तब तक तुर्की की कंपनी मायल काम करती रहेगी।

डीआईजी के आदेश पर मशरख के इंस्पेक्टर अशोक कुमार निलंबित

छपरा।

सारण पुलिस ने मशरख अंचल के इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक शख्स की शिकायत पर की गई। इंस्पेक्टर अशोक पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने और अनुसंधान को प्रभावित करने का आरोप था। सारण के एसएसपी ने बताया कि इंस्पेक्टर अशोक सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। शिकायतकर्ता कृष्णा सिंह ने आरोप लगाया था कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मामले की जांच को गलत तरीके से प्रभावित किया। शिकायत के बाद मढ़ौरा-2 के एसडीपीओ को जांच सौंपी गई। जांच में पाया कि अशोक कुमार सिंह ने पद का दुरुपयोग कर मनमानी पर्यवेक्षण टिप्पणी दी थी। ग्रामीण एसपी शिखर चौधरी ने यह रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंपी। डीआईजी सारण क्षेत्र छपरा ने एसएसपी की अनुशंसा पर अशोक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ते पर रखा गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अनुशासनहीनता या पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।

हैदराबाद में डुप्लीकेट और फेक गैजेट असेसरीज बेचने वाले गिरफ्तार

हैदराबाद। हैदराबाद में एक गैंग भंडाफोड़ हुआ है जिसने डुप्लीकेट और फेक गैजेट असेसरीज बेचने का धंधा चलाया था। हैदराबाद कमिशनर की टास्क फोर्स ने इस गैंग को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास 1 करोड़ रुपये की कीमत वाला सामान बरामद हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई फर्जी गैजेट और डुप्लीकेट मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार होने वाले गैंग को माना गया है कि वे लोगों को ओरिजनल प्रोडक्ट बताकर फेक आइटम बेच रहे थे, जिसमें सस्ते फोन और डुप्लीकेट असेसरीज शामिल थे। साथ ही, गैंग सस्ते प्रोडक्ट पर एप्पल ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर रहा था, जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। पुलिस ने इसके साथ इमेजी नंबर चेक करने की सलाह दी है और प्रोडक्ट की बिल्ड विश्लेषण के माध्यम से भी उसकी पहचान की जा सकती है।

ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता पर हिन्दुस्तान शिवसेना ने निकाली भगवा बाईक रैली

*केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक-राजा भईया

*हिन्दुस्तान शिवसेना ने बढ़ाया भारतीय सैनिकों का होंसला

नई दिल्ली। पिछले दिनों पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने और देश का गौरव बढ़ा कर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाली भारतीय सेना के सम्मान में आज हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भईया के नेतृत्व में सैंकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडों के साथ भगवा बाईक रैली निकाली, रैली प्रदेश के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों व बाजारों से होती हुई साम को श्री हनुमान मंदिर गोकलपुरी पर सम्पन्न हुई रैली में बाईक सवार शिव सैनिकों ने हाथों में भगवा झंडे थाम भारत माता की जय, आतंकवाद मुर्दाबाद,भारतीय सेना जिंदाबाद, ये देश है वीर जवानों का, आदि के नारे लगाए भारतीय सेना के जोश की तरह रैली में मौजूद सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था, इस मौके पर रैली समापन के दौरान पार्टी प्रमुख राजा भईया ने सभी को संबोधित करते हुऐ कहा कि आज इस भगवा रैली का मकशद ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान वीरगती को प्राप्त हुऐ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजली देना और सेना का सम्मान बढ़ाने के लिऐ किया गया है केसरिया / भगवा रंग बलिदान का प्रतीक है और हमारे देश के सैनिकों ने आतंकवाद पर विजय प्राप्त करते हुऐ अपने कई जवानों का बलिदान दिया है उनका यह बलिदान देश के हर नागरिक पर एक कर्ज है और सदा रहेगा देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व की भी सराहना करते हुऐ उन्होंने कहा कि आज देश एक दम सुरक्षित हाथों में है तथा देश के हर वर्ग का नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है, पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे कर उन्होंने यह साबित भी कर दिया है,रैली में कविराज, सीताराम, जितेन्द्र कुमार, रमेश दिनकर, विजय महाजन, वीरेश गुप्ता, दर्शन सिंह, करतार सिंह, तेजसिंह, रामकुमार, लक्ष्य राठौर, देवेन्द्र चौधरी, मुकेश पांचाल आदि अपने अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे।

खुशखबरी, राजस्थान के 4.5 लाख पशुपालकों को एक साथ मिला सरकार का तोहफा, राशि बैंक खातों में जमा

जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग साढ़े चार लाख पशुपालकों के खातों में 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई है। यह राशि 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों को दूध देने वाले पशुपालकों को प्रदान की गई है।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने

के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा 2025-25 में तय 500 करोड़ रुपए की राशि का सफल भुगतान कर दिया गया है।

मंत्री कुमावत ने आगे बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल 2025 की बकाया 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यह राशि भी शीघ्र ही पात्र पशुपालकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

यह योजना न केवल पशुपालकों को आर्थिक बल प्रदान कर रही है, बल्कि राज्य के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को भी मजबूती दे रही है।

राजस्थान के कई इलाकों में 6,7 व 8 जून को नहीं बिकेगी शराब

जयपुर। राज्य सरकार ने आगामी 8 जून, 2025 को होने वाले नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनज़र संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। यह निर्णय शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ सभी पात्र ऋणी सदस्यों को दिए जाने पर फोकस

आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिन नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से पद रिक्त हुए हैं, वहां 8 जून को उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। इसके चलते संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनसे लगे 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्रों में 6 जून को शाम 5

बजे से 8 जून की शाम 5 बजे तक 48 घंटे का सूखा दिवस रहेगा। इस अवधि में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच पदों के लिए भी उपचुनाव 8 जून को ही होंगे। इन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।

यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। प्रशासन द्वारा संबंधित जिलों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि सूखा दिवस के दौरान सभी शराब की दुकानें बंद रहें और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाए।

मानसून से पहले सुनिश्चित हों बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव के समस्त आवश्यक इंतजाम

*जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये निर्देश

* जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को मानसून सीजन से पहले बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हैरिटेज के अधिकारियों को सिवरेज एवं नालों की गुणवत्तापूर्ण सफाई का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने, सफाई के बाद सड़क पर जमा कीचड़ एवं गंदगी का उठाव करवाने, खुले सिवरेज के खुले चैंबर्स और मेनहोल पर ढक्कन लगावाने एवं नालों पर फैरो कवर लगवाने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के साथ-साथ मिट्टी के कट्टों, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों, जेसीबी, पोकलेन, मडपंप, सहित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ढीले तारों को कसने, झुके हुए बिजली के पोलों को सीधा करने, खुले फीडरों बंद करने, खुले तारों को दुरुस्त करने एवं लो-लाइन पैनल बॉक्स एवं ट्रांसफार्मर को ऊंचाई पर लगवाने एवं मानसून सीजन के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पाइप लाइन की लीकेज दुरुस्त करने, आवश्यकता होने पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी बांधों पर सहज दृश्य एवं बड़े अक्षरों में अंकित चेतावनी बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी छोटे बड़े तालाबों पर चेतावनी बोर्ड लगावाने के निर्देश दिये। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रपट क्षेत्र एवं लो-लाइन एरिया की टूट, रेलिंग एवं जंजीर को दुरुस्त करवाने, बांधों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिवृष्टि होने पर भूमि कटाव और जलभराव से निपटने एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता रखी जाए।

जिला कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने यहां बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर ले एवं उन पर पूरी जानकारी रखने वाले अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, वन विभाग, नगर निगम, जेडीए, जयपुर मैट्रो, गृह सुरक्षा, शिक्षा, पशुपालन सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों को भी मानसून के दौरान विभागीय स्तर पर अपेक्षित समस्त इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री संतोष कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री गोपाल सिंह शेखावत सहित, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद बंदी की संदिग्ध मौत, अब हनुमान बेनीवाल ने लगाया बड़ा आरोप

जोधपुर। बाइक चोरी के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन ने मौत पर अंदेशा जताया। रातानाडा थाने में मर्ग दर्ज करने के बाद अब न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करेंगे।

वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि परिजन की मानें तो नथमल से पहले कापरड़ा और फिर रातानाडा थाने में मारपीट की गई थी। जेल में भी मारपीट की गई थी। पुलिस ने बिना मेडिकल कराए कोर्ट में पेश किया था। आइजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी बनाकर व जज की मॉनिटरिंग में जांच की जाए। इस बारे में डीजीपी से बात की है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग को अवगत करवाया है। यह प्रकरण सरकारी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है।

डीसीपी का दावा, मेडिकल कराया था

सांसद हनुमान बेनीवाल के ट्वीट के बाद पुलिस उपायुक्त (पूर्व) आलोक श्रीवास्तव ने प्रकरण में लिखित में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि नथमल ने प्रवीण सिंह के साथ मिलकर बाइक चुराई थी। 23 व 24 को नथमल को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर कोर्ट में पेश किया गया था। एसीजेएम-7 जोधपुर महानगर न्यायिक जांच कर रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंपा गया है।

बाइक चोरी का आरोप

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि कापरड़ा थानान्तर्गत रावर गांव निवासी नथमल (31) को कापरड़ा थाना पुलिस ने 22 मई को बाइक सहित पकड़ा था। जांच में बाइक चोरी की पाई गई थी। ऐप से मोबाइल नम्बर मिलने पर बाइक मालिक से सम्पर्क करने पर बाइक के चोरी की होने और रातानाडा थाने में एफआइआर दर्ज कराए जाने का पता लगा था। कापरड़ा थाना पुलिस ने नथमल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर रातानाडा थाना पुलिस को सूचित किया था।

जेल में बिगड़ी तबीयत

जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल भगाराम ने 21 मई को कापरड़ा से रावर निवासी नथमल को गिरफ्तार किया था। 23 मई को कोर्ट ने एक दिन रिमाण्ड पर भेजा था। कापरड़ा थाने से चोरी की बाइक बरामद करने के साथ ही वारदातस्थल की तस्दीक कराई गई थी। 24 मई को उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

इस बीच, सोमवार देर रात जेल में उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जेल डिस्पेंसरी में जांच के बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मध्यरात्रि उसकी मृत्यु हो गई थी। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया। मंगलवार सुबह जेल प्रशासन ने मर्ग दर्ज कराया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंपा गया।

मृत्यु को लेकर परिजन आशंकित, जांच की मांग

बंदी की मौत का पता लगने पर परिजन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। उन्होंने मृत्यु पर आशंका जताई। मारपीट करने से नथमल की मृत्यु होने का आरोप लगाया। एकबारगी उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। समझाइश के बाद पोस्टमार्टम कराया जा सका।

राजस्थान में पंचायत परिसीमन पर लगा स्टे-डोटासरा

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में है और भ्रष्टाचार चरम पर है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता और अफसरशाही मिलकर दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं, जबकि जनता की समस्याओं पर सरकार की कोई संवेदना नहीं है।

'राम भरोसे' चल रही सरकार

डोटासरा ने राज्य सरकार को 'राम भरोसे' चलने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कभी दिल्ली घूमते हैं, तो कभी देव दर्शन यात्रा पर निकल जाते हैं। विभागीय समीक्षा के नाम पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है, जबकि जनता को पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रहीं।

SI भर्ती पर सरकार की चुप्पी पर सवाल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने एसआई भर्ती को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डेढ़ साल से सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि भर्ती रद्द करनी है या बहाल रखनी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ कहती है कि लाखों को नौकरी देगी, लेकिन जो पहले से चयनित हैं, उनके भविष्य को लेकर ही अनिर्णय की स्थिति में है। पहले 400-500 भर्ती को फर्जी बताया,

अब कोर्ट में जाकर कहते हैं कि 50-55 ही गलत हैं।

डोटासरा ने कहा कि लगता है पर्ची ऊपर से आई नहीं, इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे। जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आ जाती, तब तक को निर्णय लेते नहीं हैं। ये बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है।

सेप्टिक टैंक हादसे पर भी सरकार को घेरा

वहीं, जयपुर की ज्वैलरी फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक हादसे में चार मजदूरों की मौत पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीवरेज सफाई के लिए रोबोटिक मशीनें खरीदी थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें गायब कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल पुराने कामों की समीक्षा के नाम पर समय काट रही है, लेकिन अब तक किसी समीक्षा का ठोस नतीजा नहीं निकला।

दुर्भावना से किया गया पंचायत परिसीमन

डोटासरा ने कहा कि पहली बार हाईकोर्ट ने सैकड़ों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए किसी प्रदेश सरकार के पंचायत परिसीमन पर स्टे लगाया है, जो इस बात का सबूत है कि यह निर्णय राजनीतिक हित साधने के लिए लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कैसे जीते और कांग्रेस कैसे हारे, इसी सोच के आधार पर परिसीमन किया गया।

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि जब युद्ध की स्थिति थी, तब कांग्रेस ने सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। अब जब चुनाव है तो बीजेपी तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री सेना के शौर्य के पीछे छुपकर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।

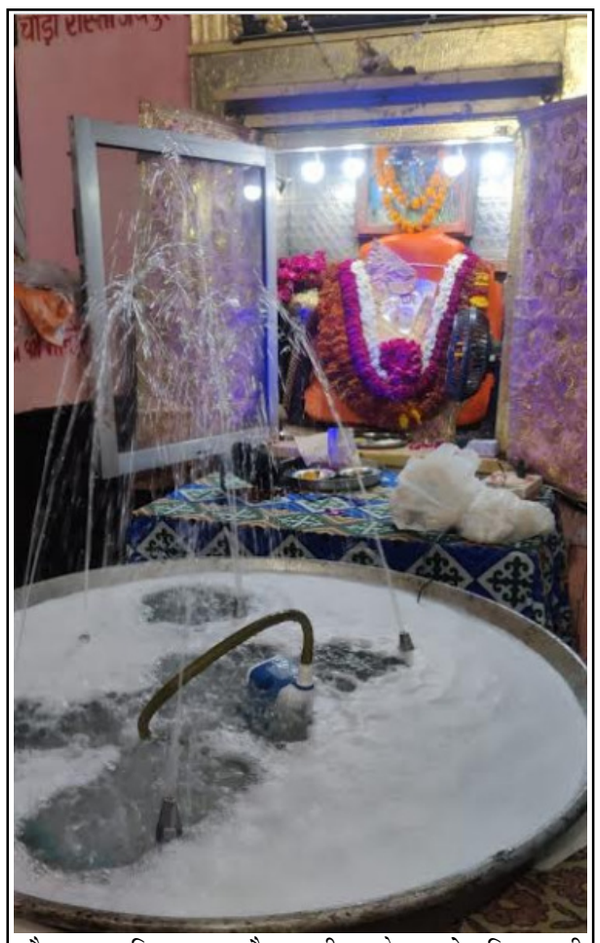

चौड़ा रास्ता स्थित अमर जैन हास्पीटल के सामने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में फव्वारा झांकी सजाई गई।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717